

प्रेषक,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2016

विषय: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको सम्बोधित प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून के पत्र संख्या लेखा/भवन निर्माण/बजट/2016-17/1399, दिनांक 22 जुलाई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग के निर्माण हेतु संशोधित आंगणन रु0 178.63लाख के उपलब्ध कराये गये है, जिसको टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रु0 148.14लाख + रु0 30.49लाख (सिविल कार्य + उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार क्रय) अर्थात् कुल रु0 178.63लाख औचित्यपूर्ण पाया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 203/XLI-1/2016-57(प्रशि0)/15, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्गत प्रथम किश्त के रूप में रु0 40.00लाख (रु0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति उक्त निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रु0 61.29 लाख (रु0 इकसठ लाख उनतीस हजार मात्र) (संलग्न विवरण के अनुसार मद संख्या-16, 30 एवं 31 से आहरित करते हुए) को अवमुक्त करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम 2013 की धारा-11(ग) में यह व्यवस्था है कि सामान्य योजनाओं में व्यय की जानी वाली ऐसी धनराशि, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लाभान्वित होती है, में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की अनुपातिक जनसंख्या के आधार पर धनराशि अनुसूचित जाति उप योजना और जनजाति उपयोजना मद से आहरित कर नियमानुसार उपयोग में लायी जायेगी।

- 3- शेष समस्त शर्तें एवं प्राविधान शासनादेश संख्या 203/XLI-1/2015-57(प्रशि0)/15 टी0सी0, दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के अनुसार यथावत् बने रहेंगे।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-00-24-वृहद निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या 30 लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण, 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 0201-आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) -00 -24-वृहद निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण, 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03-दस्तकार प्रशिक्षण योजना, 0301-आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (ट्रायबल सब प्लान)-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या -121(P)/XXVII(5)/2016, दिनांक 06.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 478 (1)/XLI-1/16 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

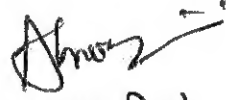
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), सर्वे चौक, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून इकाई-2, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।

क्र0सं0	मद संख्या	धनराशि (लाख में)
1	अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन- 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण-00-24-वृहद निर्माण कार्य	46.62
2.	अनुदान संख्या 30 लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण, 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 0201-आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) -00 -24-वृहद निर्माण काय	11.00
3.	अनुदान संख्या-31 लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण, 796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना, 03-दस्तकार प्रशिक्षण योजना, 0301-आच्छादित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (ट्रायबल सब प्लान)-24 वृहद निर्माण कार्य	3.67
	योग-	61.29

कुल धनराशि (रु0 इकसठ लाख उन्नतीस हजार मात्र)


(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।